

## SAARC का 40वाँ चार्टर दविस

### प्रलिस के लयि:

[दकषणि एशयिई कषेत्रीय सहयोग संगठन](#), [दकषणि एशयिई मुक्त वयापार समझौता](#), [राष्ट्रीय ज्ञान नेटवरक](#), [युरोपीय यूनयिन \(EU\)](#), [दकषणि पूरव एशयिई राष्ट्र संघ](#), [बेलट एंड रोड इनशिरिटवि](#), [बमिसटेक](#)

### मेन्स के लयि:

दकषणि एशयिई कषेत्रवाद, SAARC में भारत की भूमिका और योगदान, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग।

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

### चर्चा में क्यों?

8 दसिंबर, 2024 को [दकषणि एशयिई कषेत्रीय सहयोग संगठन \(SAARC\)](#) ने अपना 40वाँ चार्टर दविस मनाया। यह दविस SAARC की स्थापना के सम्मान में प्रतविरष मनाया जाता है।

### दकषणि एशयिई कषेत्रीय सहयोग संगठन क्या है?

- **दकषणि एशयिा में कषेत्रीय सहयोग पर** पहली बार एशयिई संबंध सम्मेलन (1947), बगुइओ सम्मेलन (1950) और कोलंबो पॉवरस सम्मेलन (1954) में चर्चा की गई थी।
  - SAARC की अवधारणा वर्ष 1980 में तब सामने आई जब **बांग्लादेश के राष्ट्रपति जयिाउर रहमान** ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लयि कषेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव रखा।
  - SAARC की आधिकारिक स्थापना **8 दसिंबर, 1985 को ढाका**, बांग्लादेश में हुई थी, जिसके **7 संस्थापक सदस्य हैं**: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकसितान और श्रीलंका।
    - वर्ष 2007 में अफगानसितान 8वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ।
- **उद्देश्य:**
  - दकषणि एशयिा में कल्याण को बढ़ावा देना तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
  - आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगत और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना।
  - सदस्य राज्यों के बीच आत्मनिर्भरता और आपसी विश्वास को मजबूत करना।
  - आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।
  - अन्य विकासशील देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।
- **प्रमुख सिद्धांत:** संप्रभु समानता, कषेत्रीय अखंडता, अहस्तकषेप, तथा सर्वसम्मति आधारित नरिणय लेना।
- **SAARC का महत्त्व:** SAARC में वर्ष 2021 तक **वशिव के भूमिकषेत्र का 3% वशिव की जनसंख्या का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5.21% (4.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर)** शामिल है।
- **सहयोग का दायरा:** SAARC के एजेंडे में **दकषणि एशयिई मुक्त वयापार समझौता (South Asian Free Trade Area- SAFTA)** शामिल है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और यह वर्ष 2006 से प्रभावी है, जिसका उद्देश्य दकषणि एशयिा में टैरफि कम करना और मुक्त वयापार को बढ़ावा देना है।
  - **SAARC एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस (SAARC Agreement on Trade in Services- SATIS)** 2012 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य अंतर-कषेत्रीय नविश को बढ़ाना तथा सेवाओं में वयापार को स्वतंत्र बनाना है।



- **साझा क्षेत्रीय समाधान: सीमा पार आतंकवाद और महामारी** जैसे मुद्दे सामूहिक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की मांग करते हैं।
  - SAARC ने पहले भी कोवडि-19 आपातकालीन कोष की स्थापना जैसी पहलों का समन्वय किया है, जिससे संकट के दौरान इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है।
- **आर्थिक एकीकरण की संभावना: 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद और लगभग 1.8 बिलियन की आबादी के साथ, दक्षिण एशिया में महत्त्वपूर्ण अपर्युक्त क्षमता है।
  - व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये SAARC के ढाँचे, जैसे कसिफ्टा और सेवाओं में व्यापार पर SAARC समझौता, को अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- **बाह्य ढाँचे पर अत्यधिक निर्भरता से बचना:** सारक की उपेक्षा करने से सदस्य राष्ट्रों को आसियान जैसे बाह्य मंचों या चीन के नेतृत्व वाली पहलों जैसे BRI पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है।
  - SAARC दक्षिण एशिया को अपने विकास पथ पर नयितरण रखने का साधन प्रदान करता है।

## SAARC में भारत का योगदान क्या है?

- **SAARC शिखर सम्मेलन:** भारत ने अठारह SAARC शिखर सम्मेलनों में से तीन की मेजबानी की है: दूसरा शिखर सम्मेलन बंगलुरु (1986), आठवाँ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली (1995) और 14 वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली (2007) में।
- **तकनीकी सहयोग:** भारत ने अपने **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network- NKN)** को श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों तक वसितारित किया है, जिससे शैक्षिक तथा तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है।
  - इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2017 में **दक्षिण एशियाई उपग्रह (South Asian Satellite- SAS)** लॉन्च किया, जो SAARC देशों को उपग्रह-आधारित सेवाएँ प्रदान करेगा।
- **मुद्रा वनिमिय व्यवस्था:** वर्ष 2019 में भारत ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से SAARC सदस्यों के लिये मुद्रा वनिमिय व्यवस्था में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के 'स्टैंडबाय स्वैप' को शामिल करने को मंजूरी दी थी।
- **आपदा प्रबंधन:** भारत गुजरात में SAARC आपदा प्रबंधन केंद्र की अंतरिम इकाई की मेजबानी करता है।
  - यह केंद्र SAARC देशों में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिये नीतितगत सलाह, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU):** भारत दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का घर है, जिसकी स्थापना 14 वें SAARC में अंतर-सरकारी समझौते के माध्यम से की गई थी।
  - यह SAARC देशों के छात्रों और विद्वानों के लिये विश्व स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है।

## SAARC को मजबूत बनाने में भारत की भूमिका

- **नेतृत्व की भूमिका:** सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत SAARC देशों के बीच क्षेत्रफल और जनसंख्या का 70% से अधिक हिस्सा बनाता है तथा लगभग सभी सदस्य देशों से रणनीतिक रूप से संबंधित हुआ है।
  - SAARC उपग्रह और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये समर्थन जैसी पहल भारत की प्रतबिद्धता को रेखांकित करती हैं।
- **प्रस्तावित उपाय:** भारत को कम विकासित SAARC देशों के लिये शुल्क मुक्त पहुँच जैसी एकतरफा रणियतें देना जारी रखना चाहिये।
  - छोटे देशों को भी भारत की प्रगतिको अपने लिये खतरा मानने के बजाय उसका लाभ अपने विकास के लिये उठाना चाहिये।
  - **BBIN मोटर वाहन समझौते** जैसी क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को मजबूत करना तथा उन्हें वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करना।
  - भारत के लिये यह आवश्यक है कि वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, साथ ही छोटे पड़ोसियों के बीच "बगि बरदर" की धारणा को भी नयितरित करना।
    - क्वाड और हदि-प्रशांत साझेदारी जैसे मंचों का उपयोग बाहरी दबावों को संतुलित करने और क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
  - भारत पाकस्तान को दरकिनार करते हुए दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिये बमिस्टेक का भी उपयोग कर सकता है।
  - छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन-केंद्रित पहलों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।

## SAARC के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **राजनीतिक तनाव एवं द्विपक्षीय संघर्ष:** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा जनसंख्या के मामले में भारत और पाकस्तान SAARC में प्रभावी भूमिका में हैं लेकिन आतंकवाद एवं क्षेत्रीय विवाद जैसे मुद्दों सहित इनके बीच तनावपूर्ण संबंध, सहयोग में बाधक हैं।
  - सीमापार आतंकवाद से निपटने में पाकस्तान की नषिक्रयिता के कारण भारत ने वर्ष 2016 में 19वें SAARC शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप इसे स्थगित कर दिया गया।
  - 18वाँ SAARC शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में काठमांडू में आयोजित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप 36-स्तरीय काठमांडू घोषणापत्र लाया गया था।
  - बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकस्तान सहित कई सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता तथा शासन संबंधी समस्याओं के कारण दीर्घकालिक क्षेत्रीय नयिोजन में बाधा आती है।
- **नमिन आर्थिक एकीकरण:** SAARC देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय व्यापार उनके कुल व्यापार का केवल 5% है जबकि युरोपीय संघ (EU) में

यह 65% और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ में 26% है।

- SAFTA के सीमिति कार्यान्वयन तथा उत्पाद वविधिीकरण की कमी से आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है।
- असममति विकास: भारत के प्रभुत्व से अक्सर इसे "बगि ब्रदर सडिरोम" की संज्ञा दयि जाने से छोटे देशों के बीच अविश्वास पैदा होता है।
  - छोटे सदस्य देश अक्सर भारत को बहुत अधिक प्रभावशाली मानते हैं जिससे इनके द्वारा भारतीय पहलों का वरिोध कयिा जाता है। इस धारणा से सामूहिक कार्रवाई हतोत्साहति होने के साथ चीन जैसी बाहरी शक्तियों पर नरिभरता में वृद्धि होती है।
  - नेपाल, भूटान और मालदीव बुनयिादी ढाँचे की कमी के साथ सीमिति संसाधनों से ग्रस्त हैं।
- संस्थागत कमजोरियों: SAARC के चार्टर में नरिणयों हेतु सर्वसम्मति की आवश्यकता होने से कोई भी सदस्य प्रगतशील मुद्दों से संबंधित प्रगतिको रोक सकता है।
  - पाकस्तितान ने अक्सर इस तंत्र का उपयोग SAARC मोटर वाहन एवं रेलवे समझौतों जैसे समझौतों को अवरुद्ध करने के लयि कयिा है।
  - चीन, यूरोपीय संघ एवं अमेरिका जैसे पर्यवेक्षकों की भूमिकाओं के बारे में स्पष्टता का अभाव होने से बाहरी समर्थन सीमिति रहा है।
  - वविादासपद द्वपिकषीय मामलों को अलग रखने से कषेत्रीय तनाव के मूल कारणों का समाधान करने की SAARC की कषमता सीमिति हुई है। इससे वविादों को सुलझाने में संगठन की प्रासंगकितता कमजोर हुई है।
- बाह्य प्रभाव: बेल्ट एंड रोड इनरििटिवि (BRI) के माध्यम से चीन की बढ़ती उपस्थति एवं श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकस्तितान में इसके रणनीतिक नविश से SAARC देशों के बीच गतशीलता जटलि हुई है।
  - चीन-पाकस्तितान आर्थिक गलयिरा (CPEC) तथा हंबनटोटा बंदरगाह के विकास से चीन के प्रभाव में वृद्धि हुई है।

## आगे की राह

- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना: SATIS के परिचालन में तीव्रता लाना।
  - बुनयिादी ढाँचा, स्वास्थय सेवा तथा शक्तिषा से संबंधित कषेत्रीय परयिोजनाओं को समर्थन देने के क्रम में SAARC विकास कोष जैसी पहलों का वस्तितार करना चाहयि।
- राजनीतिक संघर्षों का समाधान: SAARC के तहत मध्यस्थता तंत्र से द्वपिकषीय तनावों को दूर करने में सहायता मलि सकती है। शक्तिषावदियों, व्यापारिक समूहों एवं नागरिक समाज को शामिल करते हुए ट्रैक-II कूटनीतिको बढ़ावा देना चाहयि।
  - ट्रैक II कूटनीतिको तनाव कम करने के क्रम में वारता तथा कार्रशालाओं के माध्यम से संघर्षों को हल करने का एक अनौपचारिक, गैर-सरकारी दृष्टिकोण है।
- आपदा प्रबंधन, शक्तिषा तथा लोक स्वास्थय जैसे मुद्दों (जो राजनीतिक रूप से कम संवेदनशील हैं) को प्राथमकितता देनी चाहयि।
- उप-कषेत्रीय समूहों का लाभ उठाना: BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) और BIMSTEC (बहु-कषेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लयि बंगाल की खाडी पहल) जैसी पहल SAARC के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ वशिवास को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं।
- गैर-पारंपरिक सुरकषा खतरों का समाधान करना: आतंकवाद-रोधी तथा आपदा प्रबंधन हेतु कषेत्रीय सहयोग को मज़बूत बनाने के साथ सदस्य देशों के बीच खुफिया-साझाकरण ढाँचे को बढ़ावा देना चाहयि।
- संस्थागत तंत्र में सुधार: कसिी एक देश द्वारा प्रगत में बाधा डालने को रोकने के लयिसर्वसम्मति आधारित नरिणय लेने के मॉडल को भारत मतदान द्वारा प्रतसिथापति करना चाहयि।
  - SAARC सचविालय को अधिक स्वायत्तता तथा वत्तितय संसाधन देने के माध्यम से इसे मज़बूत बनाना चाहयि।
- युवा भागीदारी को प्रोत्साहति करना: दक्षिण एशयिाई वशि्वविद्यालय और अन्य कषेत्रीय मंचों के माध्यम से छात्र आदान-प्रदान, छात्रवृत्त तथा युवा-केंद्रित विकास कार्रक्रमों को बढ़ावा देकर दक्षिण एशयिा के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना चाहयि।

## नषिकरष

राजनीतिक तनाव और कम आर्थिक एकीकरण जैसी चुनौतियों के बावजूद SAARC, कषेत्रीय सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच बना हुआ है। भारत का बढ़ता नेतृत्व इस संगठन की कषमता को मज़बूत कर सकता है। SAARC की पूरी कषमता का उपयोग करने के लयि हमें आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, राजनीतिक संघर्षों का समाधान करने एवं उप-कषेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहयि।

????? ???? ???? ???? ????:

प्रश्न: दक्षिण एशयिा में कषेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में SAARC की भूमिका पर चर्चा कीजयि। आर्थिक एकीकरण प्राप्त करने के क्रम में इसकी प्रभावशीलता के समकष कौन सी चुनौतियाँ बाधक हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????:

Q. "भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकस्तितान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तकषेप SAARC (दक्षिण एशयिाई कषेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लयि सहायक नहीं है।" उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजयि। (2016)

